



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2009/वैशाख 8, 1931

No. 672]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2009/VAISAKHA 8, 1931

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2009

का.आ. 1061(अ).—लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 27 अप्रैल, 2009 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

“माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष
संसद भवन, नई दिल्ली

श्री बसुदेव आचार्य,
नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),
लोक सभा,
21, अशोक रोड,
नई दिल्ली-110 001

... याची

बनाम

श्री अबु अयीश मंडल,
संसद सदस्य (लोक सभा),
221, वी. पी. हाउस, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110 001

... प्रत्यर्थी

के मामले में :

आदेश :

1. यह आवेदन लोक सभा के माननीय संसद सदस्य श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पश्चिम बंगाल में कटवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का

प्रतिनिधित्व कर रहे लोक सभा के माननीय संसद सदस्य श्री अबु अयीश मंडल के विरुद्ध 13 मार्च, 2009 को दाखिल किया गया है, जिसमें इस घोषणा के संबंध में प्रार्थना की गई है कि श्री अबु अयीश मंडल भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (2) के साथ पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन निरह हो गए हैं।

2. याचिका में यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी 6 नवम्बर, 2006 को हुए उप-चुनाव में, उक्त उप-चुनाव लड़ने के लिए भा.क.पा. (मा.) द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने पर 14वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के उम्मीदवार के रूप में लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

3. याचिका में यह तर्क भी दिया गया है कि दिनांक 6 मार्च, 2009 के विभिन्न समाचारपत्रों से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उन्हें उक्त पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है तथा इस बात की घोषणा सुश्री ममता बनर्जी द्वारा 5 मार्च, 2009 को हुई प्रैस कॉन्फ्रेंस में की गई है। याची ने अपने तर्क की पुष्टि में कुछ समाचारपत्रों की कतरनें याचिका के साथ संलग्न की हैं।

4. याची के अनुसार चूंकि प्रत्यर्थी को भा. क. पा. (मा.) द्वारा उम्मीदवारी दिए जाने पर 14वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था और अब उसने एक अन्य राजनीतिक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है, इसलिए वह वर्तमान लोक सभा का सदस्य बने रहने से निरह हो गए हैं।

5. उपर्युक्तानुसार, याची ने याचिका में कतिपय समाचारपत्रों की प्रतियां संलग्न की हैं, जिनका समाचारपत्रों की विषय-वस्तु के साथ याची द्वारा सम्यक् सत्यापन किया गया है।

6. प्रत्यर्थी ने अपना उत्तर दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की जो स्वीकार कर ली गई, अन्ततः उन्होंने अपना उत्तर

15 अप्रैल, 2009 को प्रस्तुत किया जिसमें प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया है कि उन्हें भा.क.पा. (मा.) ने 5 मार्च, 2009 को अपनी सदस्यता से निष्कासित कर दिया है और वे भा. क. पा. (मा.) नेतृत्व से “परेशान और असंतुष्ट” थे। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने पार्टी के विरुद्ध अलग-अलग मंचों से बोला है, जिस पर उनके अनुसार निरर्हता के लिए विधि के उपबंध लागू नहीं होते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है बल्कि उन्हें निष्कासित किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है और न ही किसी अन्य पार्टी के लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्रशंसा ही की है, और उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठायी है, बल्कि उनके अनुसार, इन सब बातों का निरर्हता से कोई लेना-देना नहीं है तथा अधिनियम/नियमों/न्यायालयों के निर्णय के अनुसार वह उसी पार्टी से संबंधित है, जिसने उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए खड़ा किया था।

7. याची ने एक वी.सी.डी. भी प्रस्तुत की है जिसमें 5 मार्च, 2009 को आयोजित पूर्व उल्लिखित प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड दर्ज है, जिसकी एक प्रति प्रत्यर्थी को दी गई थी जैसा कि उनके प्रतिनिधि ने इसमें इसके पश्चात् स्वीकार किया है।

8. पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए जाने की दृष्टि से मैंने इस मामले में 17 अप्रैल, 2009 की तारीख नियत की थी, लेकिन उस तारीख को प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र में किए गए अनुरोध के इस आधार पर कि वह बीमार है, मैंने सुनवाई 24 अप्रैल, 2009 तक स्थगित कर दी, यद्यपि याची के वकील और प्रतिनिधि उपस्थित थे और निर्देश दिया कि यदि अपनी अस्वस्थता के कारण प्रत्यर्थी उपस्थित होने में असमर्थ है तो उन्हें अपनी ओर से सुनवाई में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजने का अवसर मिलेगा।

9. 24 अप्रैल, 2009 को हुई सुनवाई में याची का प्रतिनिधित्व श्री डी. के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री शांतो मुखर्जी, अधिवक्ता तथा श्री दीपांकर दास, पत्रकार ने किया। प्रत्यर्थी के विधि वत् प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक गुहा भी उपस्थित थे।

10. सुनवाई में, यचिका में उठाए गए मामले पर श्री अग्रवाल ने निवेदन किए और कतिपय समाचारपत्र कतरनों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया जिनकी प्रतियां याचिका के साथ संलग्न हैं। उन्होंने श्री दीपांकर दास, जो एक समाचारपत्र के पत्रकार हैं और माननीय संसद सदस्य तथा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी ममता बनर्जी के आवास पर 5 मार्च, 2009 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, को साक्षी के रूप में बुलाया। श्री दास ने उन कार्यवाहियों का उल्लेख किया जो घटित हुई थीं जिनमें कुमारी ममता बनर्जी ने यह कहा था कि प्रत्यर्थी ने भा. क. पा. (मा.) को छोड़ दिया है तथा उनकी पार्टी की सदस्यता ले ली है और उन्होंने प्रत्यर्थी को अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया है। श्री दास के अनुसार, कुमारी ममता बनर्जी ने अपना बयान पहले बंगाली में और फिर अंग्रेजी में दिया। साक्षी ने यह भी कहा कि कुमारी ममता बनर्जी के बयान के बाद प्रत्यर्थी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के विरुद्ध कुछ टिप्पणियां की। साक्षी ने 5 मार्च, 2009 की शाम को आयोजित प्रेस सम्मेलन की कार्यवाहियों की वीसीडी रिकार्डिंग तथा समाचारपत्रों में 6 मार्च, 2009 को इस संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों का उल्लेख किया।

11. मैंने याची के वकील को वीसीडी चलाने की अनुमति दी जो प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि श्री गुहा की उपस्थिति में किया गया। श्री गुहा ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें वीडियो सीडी की एक प्रति प्राप्त हुई थी। यद्यपि वीसीडी की ध्वनि बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन जो सुना जा सकता था, उससे लोक सभा सचिवालय द्वारा तैयार किए गए प्रतिलेख से ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्यर्थी प्रेस सम्मेलन में माननीय संसद सदस्य और तृणमूल कांग्रेस की नेता कुमारी ममता बनर्जी के बगल में बैठे थे जिन्होंने यह उल्लेख किया कि उन्होंने प्रत्यर्थी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और वे उनके पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि भा. क. पा. (मा.) में जो लोग थे और जिन्होंने साम्यवादी आंदोलन को मूर्त रूप दिया था, अब साम्यवाद पर आस्था नहीं रखते हैं और प्रमुख साम्यवादी नेताओं जैसे अबु अय्यीश मंडल उस पार्टी में नहीं रह सकते थे और उन्होंने उन्हें टिकट नहीं दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी प्रत्यर्थी को अच्छी तरह पहचानती है और उनकी संगठनात्मक क्षमता और अन्य गुणों की सराहना करती है और यह कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रत्यर्थी का स्वागत किया तथा उनका न केवल हार्दिक रूप से स्वागत किया गया है बल्कि उन्हें उनकी पार्टी की राज्य समिति के एक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी किया गया है और वे प्रत्यर्थी को पश्चिम बंगाल के प्रत्येक गांव में ले जाएंगी।

12. प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रेस सम्मेलन में और जैसाकि सीडी में रिकॉर्ड किया गया है, बताया कि उनकी पार्टी भा.क.पा. (मा.) ने उन्हें निर्वाचन हेतु नामांकन से अलग किया है जिसके बारे में उन्हें समाचारपत्रों से जानकारी मिली थी और यह भी कि उन्होंने इसके विरुद्ध पार्टी के भीतर बहादुरी से अपनी आवाज उठाई थी।

13. सुनवाई के दौरान याची के विद्वान अधिवक्ता ने दसवीं अनुसूची के उपबंधों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(2) के उपबंधों और जी. विश्वनाथन बनाम माननीय अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो एआईआर 1996 एससी 1960 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की गई है कि “ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) के स्पष्टीकरण में यह उपबंध है कि सभा का कोई निर्वाचित सदस्य उस राजनीतिक दल, यदि कोई हो, से संबंधित माना जाएगा जिसने उसे सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, ऐसा व्यक्ति जिसे उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया था और जिसे सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था, उसी पार्टी से संबंधित रहेगा। इसके बावजूद ऐसे किसी सदस्य को पार्टी से निकाल दिया गया है अथवा निष्कासित किया गया है, वह दसवीं अनुसूची के प्रयोजनार्थ उसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना रहेगा जिसने उसे निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया हो। उसे ‘असंबद्ध’ माने जाने के बावजूद वह उसी राजनीतिक पार्टी में बना रहेगा। आगे प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति कब ऐसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता का ‘स्वेच्छा से त्याग’ करता है जैसाकि पैरा 2 (1) (क) में उपबंध किया गया है? राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागने का कार्य स्पष्ट अथवा निहित हो सकता है। ऐसा कोई सदस्य जिसे किसी पार्टी द्वारा उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया है और जो निर्वाचित हुआ है, उसे उस पार्टी द्वारा

निकाला गया है अथवा निष्कासित किया गया है, वह किसी दूसरी (नई) पार्टी में शामिल होता है, तो वह निश्चित रूप से उस राजनीतिक पार्टी की सदस्यता से स्वेच्छिक त्यागपत्र दिए जाने का मामला बनता है जिसने ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए उसे उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया हो।" माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के आधार पर याची के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया कि प्रत्यर्थी का कोई प्रतिवाद नहीं है और भारत के संविधान के उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार वे निरह हो गए हैं।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने किहोंटा होलोहोन बनाम जाचिल्हू एवं अन्य (ए. आई. आर 1993 एससी 412) के मामले में निर्णय देते हुए निहित उद्देश्य और प्रयोजन का वर्णन किया है जिन्हें दसवीं अनुसूची द्वारा प्राप्त किया जाना है कि "दसवीं अनुसूची में यह उपबंध राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता देते हैं। एक राजनीतिक दल विशेष कार्यक्रम के साथ मतदाता के सामने जाता है और वह ऐसे कार्यक्रम के आधार पर चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करता है। इस प्रकार राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार उस राजनीतिक दल के कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचित हो जाता है। पैरा 2(1)(क) के उपबंध इस आधार पर लागू होते हैं कि राजनीतिक औचित्य और नैतिकता की मांग है कि यदि ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के पश्चात अपनी संबद्धता बदलता है और उस राजनीतिक दल को छोड़ता है जिसने उसे चुनाव के समय उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था, तो उसे विधान मंडल की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए और फिर से जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए।"

15. डा. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद और अन्य (2004) 8 एससीसी 747 के उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत "सभा के सदस्य की निरहता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष के पास है। यह नोट किया जाए कि दसवीं अनुसूची में सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष के बारे में कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया गया है। उनकी भूमिका केवल प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने तक है। एक बार एकत्रित किए गए अथवा रखे गए तथ्य दर्शाते हैं कि सभा के सदस्य ने यदि ऐसा कोई कार्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा (2) के उप-पैरा (1), (2) अथवा (3) की परिधि में आता है तो निरहता की स्थिति लागू होगी और सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष को इस संबंध में निर्णय लेना होगा।"

16. दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उल्लंघन के आरोप संबंधी याचिका पर विचार करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी ऐसी अधिकारिक उद्घोषण को देखते हुए अध्यक्ष की भूमिका एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में केवल तथ्य का पता लगाने के क्षेत्र में है तथा जब एक बार तथ्य इकट्ठे कर लिए जाते हैं या दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अर्थ के अंदर अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित रूप में कुछ कार्यवाही दर्शाने के लिए रखे जाते हैं तो सभा के अध्यक्ष को इस आशय का निर्णय लेना होगा तथा उन्हें इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं होगा।

17. वर्तमान मामले में याची ने श्री दास जो प्रेस कान्फ्रेंस में

उपस्थित थे, के साक्ष्य के अलावा पहले उल्लिखित वीसीडी और साथ ही याचिका के साथ सलग्न समाचारपत्र की कतरनों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बालकृष्ण बनाम जार्ज फर्नांडीज (एआईआर 1969 एससी 1201) में यह विनिर्णय दिया गया है कि "अन्य किसी भी साक्ष्य की तरह समाचार रिपोर्ट अपने आप में पूर्ण नहीं है और ऐसे साक्ष्य के अभाव में यह केवल समर्थक साक्ष्य का कार्य करती है और समाचारपत्र की रिपोर्टों पर अन्य साक्ष्यों के साथ विचार किया जा सकता है।" माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि "परिस्थितिजन्य साक्ष्य से ऐसी घटनाओं और समाचारपत्र की रिपोर्टों की विषय-वस्तु की प्रामाणिकता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निस्संदेह, परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि उनसे कोई और निष्कर्ष न निकाला जा सके।"

19. ऐसा कोई कारण नहीं है कि विभिन्न समाचारपत्रों, जिनमें 5 मार्च, 2009 को आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस की कार्रवाई के बारे में सूचना दी गई थी, ने गलत ढंग से किसी सामग्री का प्रकाशन किया हो और यदि वे गलत थे तो यह अपेक्षित था कि प्रत्यर्थी इससे इन्कार कर दे। ऐसी कोई भी अस्वीकृति जारी करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कथित रूप से दिए गए वक्तव्यों से उन्होंने इन्कार नहीं किया है। उनके बचाव से यह प्रतीत होता है कि उन्हें दल से निष्कासित किया गया था। भारत जैसे लोकतंत्र में प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर विभिन्न राजनीतिक दलों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों जैसे संसद सदस्यों के बारे में सूचना का प्रसार करने के मामले में। हमारे देश में प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और राजनीतिक घटनाओं के मामले में यह अपेक्षित है कि राजनीतिक घटनाओं के बारे में रिपोर्टें तथ्यात्मक हों। इस मामले में कोलकाता से प्रकाशित बहुत-से अग्रणी समाचारपत्रों ने वस्तुतः प्रत्यर्थी के कुमारी ममता बनर्जी, अध्यक्ष, टीएमसी की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल होने की सूचना दी। प्रत्यर्थी ने ऐसी रिपोर्टों की सत्यता पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाया। साधारणतया, मेरी राय में भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाचारपत्रों की रिपोर्टों को साक्ष्य के नियम के अनुसार पूर्णतया सिद्ध न होने के बावजूद अन्यथा सिद्ध होने तक विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि सुप्रतिष्ठित और सुस्थापित समाचारपत्रों ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध जानबूझकर रिपोर्ट गढ़ी हो अथवा 5 मार्च, 2009 की घटनाओं के बारे में असत्य और मनगढ़ंत रिपोर्टें प्रकाशित करने का षड्यंत्र रचा हो। अतः मेरी राय में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि प्रत्यर्थी द्वारा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है।

20. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्णय दिया गया है कि "अध्यक्ष की भूमिका संगत तथ्यों को अभिनिश्चित करने के क्षेत्राधिकार की परिधि में है और एक बार एकत्रित किए गए अथवा रखे गए तथ्य यह दर्शाते हैं कि सभा का कोई सदस्य जिसने ऐसा कोई भी कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (1), (2) अथवा (3) के क्षेत्राधिकार में आता है तो उस पर निरहता लागू होगी और सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष को इस आशय का निर्णय लेना होगा।"

21. मेरी राय में वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी द्वारा वास्तव में कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर और उपर्युक्त कारणों के चलते मुझे यह विनिर्णय देने में कोई झिझक नहीं है कि प्रत्यर्थी याचिका में यथाउल्लिखित 5 मार्च, 2009 को हुई घटनाओं के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अंतर्गत निरह हो गया है। इन तर्कों के आधार पर मैं विनिर्णय देता हूँ कि श्री अबु अयोश मंडल, पश्चिम बंगाल के कटवा निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य 5 मार्च, 2009 को हुई घटनाओं के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अंतर्गत निरह हो गए हैं। मैं तदनुसार इस मामले पर विनिर्णय देता हूँ।

22. इस प्रकार प्रत्यर्थी 14वीं लोक सभा का सदस्य बने रहने से निरह हो गए हैं और यह घोषणा की जाती है कि उनका स्थान रिक्त हो गया है।

ह./-

सोमनाथ चटर्जी, अध्यक्ष, लोक सभा

नई दिल्ली;

दिनांक 27 अप्रैल, 2009

[सं. 46/1/2009/टी.]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2009

S.O. 1061 (E).—The following Decision dated 27th April, 2009 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:—

“BEFORE THE HON'BLE SPEAKER OF LOK SABHA PARLIAMENT HOUSE, NEW DELHI

In the matter of:

Shri Basudeb Acharia,
Leader, Communist Party of India (Marxist),
Lok Sabha,
21, Ashoka Road,
New Delhi-110001.

...Petitioner

Versus

Shri Abu Ayes Mondal,
Member of Parliament (Lok Sabha),
221, V.P. House, Rafi Marg,
New Delhi-110001.

...Respondent

ORDER

This is an application filed on 13th March, 2009 by Shri Basudeb Acharia, Hon'ble Member of Parliament of Lok Sabha against Shri Abu Ayes Mondal, Hon'ble Member of Parliament of Lok Sabha representing Katwa

Parliamentary Constituency in West Bengal praying for a declaration that Shri Abu Ayes Mondal has incurred disqualification under paragraph 2 of the Tenth Schedule read with Article 102 (2) of the Constitution of India.

2. It has been contended in the petition that at a bye-election held on 6th November, 2006, the Respondent was elected to the 14th Lok Sabha, having been nominated by CPI (M) to contest the said bye-election and he was elected to Lok Sabha as a candidate of the Communist Party of India (Marxist).

3. It has further been contended in the petition that from the various newspapers dated 6 March 2009, it will appear that the Respondent has joined Trinamool Congress (TMC) and has been made the Vice President of the said Party and the same has been announced by Ms. Mamata Banerjee in a Press Conference held on 5th March, 2009. The Petitioner has annexed to the petition the clippings from some newspapers to substantiate his contention.

4. According to the Petitioner as the Respondent was elected as a Member of the 14th Lok Sabha having been set up by the CPI (M) and has now joined the Trinamool Congress, another political party he has incurred disqualification for continuing as the Member of the present Lok Sabha.

5. The Petitioner, as mentioned above, annexed copies of certain newspapers in the Petition, which along with the contents of the newspapers have been duly verified by the Petitioner.

6. The Respondent asked for extension of time to file his reply, which was granted, ultimately submitted the same on 15th April, 2009, in which the Respondent has stated, inter alia, that he has been expelled by CPI (M) from its membership with effect from 5th March, 2009 and that he had been “heckled and dissatisfied” by the CPI (M) leadership. He has admitted that he has spoken at different forums against the Party, which according to him do not attract the provisions of law for disqualification. He has further stated that he has not left the Party but has been expelled. He has further contended that he has not taken membership of any political party and has praised the aims/objects of another party, has raised voice against his own party's policies, but all these, according to him, have nothing to do with the disqualification and according to Act Rules/decision of the courts, he belongs to the Party which set him up for election as MP.

7. The Petitioner also has submitted a VCD, containing the record of the Press Conference mentioned before held on 5th March, 2009, a copy of which was given to the Respondent as was admitted by his representative as mentioned hereinafter.

8. With a view to giving opportunity of personal hearing to the Parties, I fixed the date of a hearing in the matter on 17th April, 2009 but on that date at the

request of the Respondent made by his letter, on the ground that he was ill, I adjourned the hearing, although the Petitioner's lawyer and representative were present, till 24th April, 2009 and directed that if due to his indisposition, the Respondent was unable to attend, he would have the opportunity to depute his representative to attend the hearing on his behalf.

9. At the hearing held on 24th April, 2009 the Petitioner was represented by Shri D. K. Aggarwal, Senior Advocate and Shri Shanto Mukherjee, Advocate and Shri Dipankar Das, a journalist. Shri Ashok Guha, the duly authorized representative of the Respondent was also present.

10. At the hearing, Shri Aggarwal made submissions on the case made out in the petition and drew my attention to certain newspaper clippings, the copies whereof are annexed to the Petition. He called Shri Dipankar Das as a witness, who is a newspaper reporter and was present at the Press Conference held on 5th March, 2009 at the residence of Kumari Mamata Banerjee, an Hon'ble Member of Parliament and Chairperson of Trinamool Congress. Shri Das referred to the proceedings that had taken place at which Kumari Mamata Banerjee had stated that the Respondent had left CPI (M) and joined her Party and that she had made the Respondent Vice President of her Party. According to Shri Das, Kumari Mamata Banerjee made her statement in Bengali followed by English. The witness further stated, that after her statement the Respondent made some comments against the Communist Party of India (Marxist). The witness referred to a VCD recording of the proceedings of the Press Conference held in the evening of 5th March, 2009 and to the reports which appeared in the press on 6 March, 2009.

11. I gave permission to the Petitioner's lawyer to play the VCD, which was done in the presence of the Shri Guha, the representative of the Respondent. Shri Guha also admitted that he had received a copy of the video CD. Although the audio quality of the VCD was not very good but from the transcript made by the Lok Sabha Secretariat and as one could listen to, it appeared that the Respondent was present at the Press Conference sitting next to Kumari Mamata Banerjee, the Hon'ble Member of Parliament and also the leader of the Trinamool Congress, when she mentioned that she had admitted the Respondent to her Party and he would work for the Party. She further commented that those who were in CPI (M) and gave shape to the communist movement, no longer believed in communism and notable Marxist leaders, like, Abu Ayes Mondal could not continue with the party and they have denied the ticket to him. She further said that her Party knew the Respondent well and appreciated his organizational skill and other qualities and that she welcomed the Respondent on behalf of Trinamool Congress and that not only he was received cordially but also appointed as one of the Vice-presidents of the State Committee of

her Party and would take the Respondent to every village of West Bengal.

12. In his observations, as made in the Press Conference as recorded in the CD, the Respondent stated, inter alia, that he had been excluded by his Party CPI (M) from nomination for the election about which he came to know from the newspapers and that he had raised his voice against courageously within the Party.

13. During the hearing, the learned lawyer of the Petitioner drew my attention to the provisions of the Tenth Schedule and to the provisions of Article 102 (2) of the Constitution of India and also to a judgment of the Hon'ble Supreme Court in the matter of *G. Viswanathan v. The Hon'ble Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly* reported in AIR 1996 SC 1060, in which it has been observed, inter alia, that "it appears that since the explanation to paragraph 2(1) of the Tenth Schedule provides that an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member, such person so set up as a candidate and elected as a member shall continue to belong to that party. Even if such a member is thrown out or expelled from the party, for the purposes of the Tenth Schedule he will not cease to be a member of the political party that had set him up as a candidate for the election. He will continue to belong to that political party even if he is treated as 'unattached'. The further question is when does a person 'voluntarily give up' his membership of such political party, as provided in paragraph 2 (1) (a) ? The act of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied. When a person who has been thrown out or expelled, from the party which set him up as a candidate and got elected, joins another (new) party, it will certainly amount to his voluntarily giving up the membership of the political party which had set him up as a candidate for election as such member." In reliance on the above decision of the Hon'ble Supreme Court, the Learned Lawyer of the Petitioner contended that the Respondent has no defence and that he stands disqualified under the above provisions of the Constitution of India,

14. The Hon'ble Supreme Court has been pleased to explain the underlying object and purpose, which the Tenth Schedule seeks to achieve, while delivering the judgment in the case of *Kihota Hollohon v. Zachilhu & Ors.* (AIR 1993 SC 412) that "these provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process. A political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme. A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of paragraph 2 (1) (a) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person, after the election, changes his affiliation and leaves the

political party which had set him up as a candidate at the election, then he should give up his membership of the legislature and go back before the electorate.”

15. In the decision of Dr. Mahachandra Prasad Singh v. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. (2004) 8 SCC 747, the Supreme Court has been pleased to observe that under the Tenth Schedule, “the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraphs (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect.”

16. In view of such authoritative pronouncements by the Hon'ble Supreme Court, while deciding the petition in which the allegation is of the violation of the paragraph 2(1) (a) of the Tenth Schedule, the role of the Speaker, as the designated authority, is only in the domain of ascertaining the facts and once the facts are gathered or placed to show some action, express or implied within the meaning of paragraph 2(1) (a) of the Tenth Schedule, the Speaker of the House will have to make a decision to that effect and will have no discretion in the matter.

17. In the present case, apart from the evidence of Shri Das, who was present at the Press Conference, the Petitioner has produced evidence by means of VCD mentioned before and also newspaper clippings annexed to the Petition.

18. It has been held by the Hon'ble Supreme Court in Balakrishana V. George Fernandes (AIR 1969 SC 1201) that “like any other evidence, a news report does not prove itself and without such proof it only offers a secondary evidence and newspaper reports may be taken into account with other evidence”. The Supreme Court has been further pleased to hold that “from circumstantial evidence an inference can be drawn about the happening of such events and about the truth of the contents of newspaper reports. Of course, the circumstances must be such that will not admit of any other explanation.”

19. There is no reason why the different newspapers, which reported about the proceedings of the Press Conference held on 5th March, 2009, should have published something wrongly and that if they were wrong then it was expected that the Respondent forthwith would have denied it. No step was taken to issue any denial. The statements attributed to the Respondent had not been denied by him. His defence appears to be that he was expelled from the Party. In a democracy like ours, the Press plays a very vital role,

specially in disseminating information regarding different political parties and persons in public life, as the MPs are. In our country, there is complete freedom of Press and in matters of political events, it is expected that reports about political events would be factual. In this case many of the leading newspapers published from Kolkata, in fact, reported about the Respondent joining the Trinamool Congress (TMC) in the presence of Kumari Mamata Banerjee, President, TMC. The Respondent never disputed the correctness of such reports. Ordinarily, in my view in a democratic set up like ours, the newspaper reports, though not strictly proved as per the law of evidence, can be taken as providing reliable circumstantial evidence, unless proved otherwise. There is no explanation why newspapers of great reputation and which are well established, should deliberately concoct the report against the Respondent or why they should conspire to publish false and imaginary reports about the events of 5th March, 2009. Therefore, in my opinion, there are more than sufficient materials to come to a finding in the matter about the Respondent violating the provisions of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

20. As has been held by the Hon'ble Supreme Court that “the role of the Speaker is in the domain of ascertaining the relevant facts and once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraphs (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect.”

21. In my opinion, really no answer has been provided by the respondent in the present case and on the available materials and for the reasons aforesaid, I have no hesitation in holding that the respondent in fact has incurred disqualification under paragraph 2(1) (a) of the Tenth Schedule by reason of the events which took place on 5th March, 2009, as mentioned in the petition. In the premises, I hold that Shri Abu Ayes Mondal, an elected Member of Lok Sabha from Katwa constituency of West Bengal has incurred disqualification under paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule by the reason of the events of 5th March, 2009. I decided the matter accordingly.

22. Thus the respondent stands disqualified for continuing as a member of the Fourteenth Lok Sabha and it is declared that his seat has fallen vacant

Sd./-

SOMNATH CHATTERJEE
SPEAKER, LOK SABHA

New Delhi;
Dated the 27th April, 2009

[No. 46/1/2009/T.]

P. D. T. ACHARY, Secy. General